रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 28 अक्तूबर, 1983/6 कार्तिक, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अक्तूबर, 1983

क्रमांक एल० एल० आर०-डी० (6) 17/83.—हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अध्यादेश, 1983 (1983 का अध्यादेश संख्यांक 7) जैसा कि राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश, द्वारा "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अन्तर्गत दिनांक 28 अक्तूबर, 1983 को प्रख्यापित किया गया, को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) में अपेक्षित अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित एतद्द्वारा सर्व-साधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

वेद प्रकाश भटनागर,
सचिव।

2013-राजपत्र/83-28-10-83—1,148.

मूल्य : 20 पैसे ।

1982 का अध्यादेश सं0 7.

हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अध्यादेश, 1983

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित

राज्य या लोक उपक्रमों या स्थानीय प्राधिकरणों, सहकारी समितियों या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त या द्वारा स्थापित अन्य संस्थाओं या संगठनों के कार्यों के सम्बन्ध में सेवारत व्यक्तियों द्वारा और राज्य सरकार और उपर्युक्त निकायों के साथ व्यवहार में कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण के उन्मूलन और प्रभावकारी निवारण के उद्देश्य से उनमें लगे व्यक्तियों को दण्डित करने तथा उनसे सम्बद्ध अन्य प्रकीर्ण विषयों के लिए उपबंध करने के लिए, अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है ;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

और यतः अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति महोदय के अनुदेश प्राप्त कर लिए गये हैं ;

अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अध्यादेश, 1983 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

परिभाषाएं

2. इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "स्थानीय प्राधिकरण" से कोई लोक उपक्रम, प्राधिकरण, सहकारी समिति निगम, निकाय, बोर्ड, समिति या संगठन अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो जो कि,—

(i) राज्य सरकार द्वारा निगमित या स्थापित किया गया है, या

(ii) राज्य सरकार की किसी विधि, अध्यादेश, अधिनियम, नियम या विनियम के अधीन गठित किया गया है, या

(iii) किसी केन्द्रीय अधिनियम, अध्यादेश, नियम, या विनियम के अधीन गठित किया गया है, जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण और प्राधिकार है,

(ख) "अधिकारी" से राज्य, स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने वाली या द्वारा स्थापित अन्य किसी संस्था या संगठन के कार्यों के सम्बन्ध में सेवारत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

1956 का 1. (ग) 'लोक उपक्रम' से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त शेयर पूंजी का इकावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, या ऐसी कम्पनी की समनुषंगी कम्पनी जिसमें समादत्त शेयर पूंजी का इकावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित हो, अभिप्रेत है और कोई निगम या अन्य कानूनी निकाय चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जो प्रत्येक दशा में राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में है, और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन की कम्पनी के अतिरिक्त की कोई ऐसी सरकारी कम्पनी जिसमें राज्य सरकार ने साधारण केन्द्रीय अभिदाय किया है भी, इसके अन्तर्गत है ।

अध्याय 2

संकर्म से सम्बन्धित अपराध

परिभाषाएं। 3. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "संनिर्माण" से संकर्म के संनिर्माण से सम्बन्ध रखने वाले सभी क्रिया-कलाप अभिप्रेत हैं और उत्खनन, भराई, समतलन तथा अन्य सम्बद्ध क्रिया-कलाप भी इसके अन्तर्गत हैं ;

(ख) "ठेकेदार" से, संकर्म के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविदा के अनुसरण में निर्माण विभाग के अधीन संकर्म के निष्पादन के लिए जिम्मा लेता है और जहां संदर्भ से अपेक्षित हो, ऐसे संकर्म के निष्पादन के लिए उस द्वारा नियोजित या उसके नियंत्रण में कार्य कर रहे उप-ठेकेदार और सभी अन्य अभिकरण तथा व्यक्तिगत भी इसके अन्तर्गत हैं और पद "संकर्म संविदा" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ग) "प्रभारी अधिकारी" से, संकर्म संविदा के अधीन, संकर्म के सम्बन्ध में ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो कि संकर्म के स्थान पर मुख्यतः और प्रत्यक्षतः, यह देखने के लिए उत्तरदायी है कि संकर्म या संकर्म का विनिर्दिष्ट संभाग संकर्म संविदा के निबन्धनों, शर्तों और विनिदेशों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों या निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर, निर्गत निदेशों, अनुदेशों या संकर्म आदेश के अनुसार सम्यक् रूप से निष्पादित किया जाता है ;

(घ) "निर्माण विभाग का अधिकारी" से ऐसा अधिकारी जो निर्माण विभाग में नियोजित है तथा सर्वेक्षण, संनिर्माण, मुरम्मत, अनुरक्षण, पर्यवेक्षण, योजना, आरेखण, रूपांकन, क्रय, सामग्री की आपूर्ति, या भण्डारण, यत्नोदित या विद्युत संचालित सभी प्रकार की गाड़ियों, सयंत्र, मशीनरी, औजार, पुर्जे या अन्य सारी सामग्री या उपकरणों से सम्बद्ध है, अभिप्रेत है, चाहे पद-नाम कुछ भी हो, और संकर्म के सम्बन्ध में बिलों और अग्रिम के संदाय के लिए उत्तरदायी अधिकारी या पदधारी भी इसके अन्तर्गत हैं ;

(ङ) "पर्यवेक्षण अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसका कर्त्तव्य निर्माण विभाग में लागू निर्देशिका में अन्तर्विष्ट अनुदेशों या, समय-समय पर निर्माण विभाग द्वारा निर्गत किन्हीं आदेशों या निदेशों में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार संकर्म का पर्यवेक्षण करना है ;

(च) "संकर्म" से किसी भवन, अधिसंरचना, बान्ध, बंधारा, नहर, जलाशय, झील, सड़क, पुल, पुलियां, नलकूप सहित कुआ, कारखाना, कर्मशाला, जल प्रदाय प्रणाली, विद्युत संस्थापन प्रणाली या अन्य किसी संकर्म, जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के सर्वेक्षण, संनिर्माण, मुरम्मत या अनुरक्षण से सम्बद्ध कोई संकर्म अभिप्रेत है और उपर्युक्त किसी संकर्म के संनिर्माण, अनुरक्षण या मुरम्मत से सम्बन्धित सर्वेक्षण, योजना, आरेखण, रूपांकन, क्रय, सामग्री की आपूर्त्ति या भण्डारण, यंत्रनोदित या विद्युतचालित सभी प्रकार की गाड़ियां, यंत्र, मशीनरी, औजार, पुर्जे या अन्य सभी सामग्री और उपकरण भी इसके अन्तर्गत हैं ;

(छ) "निर्माण विभाग" से राज्य सरकारी का विभाग, लोक उपक्रम, स्थानीय प्राधिकरण, या हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1968 के अधीन पंजीकृत सहकारी समिति अभिप्रेत है जो संकर्म संविदा देता है या जिसके आदेशों, निदेशों या नियंत्रक के अधीन, संकर्म संविदा की जाती है या संकर्म किया जाता है और :— 1969 का 3.

(i) राज्य सरकार से पर्याप्त सहायता प्राप्त संस्था या संगठन जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और

(ii) राज्य सरकार द्वारा निगमित या स्थापित कोई कानूनी या अकानूनी निकाय भी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, इसके अन्तर्गत है।

संविदा आदि के उल्लघंन के लिए ठेकेदार को दण्ड।

4. जो कोई भी निर्माण विभाग के साथ की गई संकर्म संविधा का ठेकेदार होते हुए, आशय से, जान बूझकर या भ्रष्ट हेतु से संविधा के निबन्धनों के सात्विक उल्लंघन में या निर्माण विभाग या इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए मानकों, विनिदेशों, आदेशों या निदेशों की घोर अवहेलना करके इस प्रकार संकर्म का निष्पादन करता है जिससे कि संकर्म या इसके सम्भाग की गुणवत्ता, कारीगरी, मजबूती या टिकाउपन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

पर्यवेक्षण के अभाव के लिए प्रभारी अधिकारी को दण्ड ।

5. जो कोई भी, संकर्म संविधा के अधीन ठेकेदार द्वारा या अन्यथा निष्पादित किए जा रहे संकर्म का प्रभारी अधिकारी होते हुए आशय से या जानबूझ—

(i) संविदा के निबन्धनों के सात्विक उल्लंघन में, या

(ii) निर्माण विभाग या इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए मानकों, विनिर्देशों आदेशों या निदेशों की घोर अवहेलना करते हुए संकर्म की—

(क) करने की अनुज्ञा या मौनानुमति देता है, या

(ख) उसे रोकने या उसके बारे में रिपोर्ट करने में चूक करता है, या

(ग) भ्रष्ट हेतु से उसे दुष्प्रेरित करता है,

जिससे संकर्म या उसके सम्भाग की गुणवत्ता, कारीगरी, मजबूती या टिकाऊपन पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो दोनों म से एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

मिथ्या या काल्पनिक मस्टर रोल या माप-बही तैयार करने के लिए दण्ड।

6. (1) जो कोई भी संकर्म का प्रभारी अधिकारी होते हुए या लोक निर्माण विभाग का अधिकारी होते हुए, संकर्म के सम्बन्ध में आशय से या जानबूझ कर—

(क) मिथ्या या काल्पनिक मस्टर रोल तैयार करता है, या

(ख) मिथ्या या काल्पनिक माप-बही तैयार करता है, या

(ग) मिथ्या या काल्पनिक लोह या धातु, रेत, मिट्टी के मिथ्या या काल्पनिक उत्खनन के लिए संदाय करता है, या

(घ) उत्खनन के अधीन स्तर का उच्चतर दर पर संदाय करने के लिए गलत वर्गीकरण करता है, या

(ङ) बिना संकर्म के या अपर्याप्त या काल्पनिक या नकली संकर्म के लिए संदाय करता है, या

(च) नियमों और आदेशों के उल्लंघन में ऐसी दरों पर संदाय करता है जो बिल्कुल अनुपयुक्त है या जानबूझ कर अधिक संदाय करता है,

तो उसे दोनों में से एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई भी पर्यवेक्षण अधिकारी होते हुए, उप-धारा (1) के अधीन अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा उसे भी, दोनों में से एक प्रकार से कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

आपूरित सामग्री ठेकेदार द्वारा गुप्त बिक्री के लिए दण्ड।

7. जो कोई भी, संकर्म संविदा के अधीन ठेकेदार होते हुए, निर्माण विभाग द्वारा विनिर्देश के अनुसार संकर्म के लिए आपूरित सीमेण्ट, स्टील, लोहे या अन्य सामग्री को संकर्म में उचित रूप से प्रयोग करने के स्थान पर या बचे हुए सामान को निर्माण विभाग को वापिस करने के स्थान पर बेचता है या अन्यथा अन्तरित करता है, तो उसे दोनों में से एक प्रकार के कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

छल पूर्ण निविदाएं देने के लिए दण्ड।

8. जो कोई भी निर्माण विभाग के अधीन संकर्म के लिए निविदाकार होते हुए—

(क) मिथ्या या अविद्यमान या नकली व्यक्ति के नाम पर काल्पनिक प्रतियोगात्मक निविदाएं प्रस्तुत करके, संकर्म संविदा के अधीन अपने लिए या अन्य व्यक्ति के लिए संकर्म उपाप्त, या प्राप्त करता है या उपाप्त या प्राप्त करने का प्रयास करता है, या

(ख) दुरसन्धिपूर्ण निम्न दर निविदा की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ प्रतियोगिता से बचने के लिए किसी अन्य निविदाकार या निविदाकारों के साथ मिल कर षड़यंत्र करता है, या

(ग) निविदा स्वीकृत करने का प्राधिकार रखने वाले अधिकारी पर, अनुचित प्रभाव डलवाने के लिए निकट रिश्तेदारी या किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति को इसमें लगाता है या उसका सक्रिय सहयोग लेता है,

तो उसे दोनों में से एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा में निकट रिश्तेदार के पुत्र, पोता, पिता, माता, पत्नी, भाई, बहिन, बहनोई, साला, ससुर और सास, अभिप्रेत है ।

छल पूर्ण निविदा को स्वीकृत करने के लिए अधिकारी को दण्ड ।

9. जो कोई भी निर्माण विभाग की ओर से निविदा स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होते हुए—

(क) ऐसी निविदा को स्वीकृत करके या स्वीकृत करने की सिफारिश करके धारा 8 के अधीन अपराध करने की दुष्प्रेरणा करता है, या

(ख) किसी विशेष निविदाकार को लाभान्वित करने के उद्देश्य से, बेईमानी से, निविदाओं के मूल्यांकन का छल साधन करता है,

तो वह दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

सम्पत्ति के संदोष या अप्राधिकृत निपटान के लिए दण्ड ।

10. जो कोई भी निर्माण विभाग का अधिकारी होते हुए निर्माण विभाग को पर्याप्त हानि पहुंचाते हुए भण्डार से सामान, संयंत्र, मशीनरी, औजार, पुर्जे या अन्य सामग्री और उपकरणों का बेईमानी से संदोषपूर्वक या कपटपूर्वक—

(क) निपटान या अन्यथा अन्सरण करता है, या

(ख) अप्राधिकृत उपयोग की अनुज्ञा देता है, तो उसे दोनों में से एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा ।

घटिया या कम मात्रा में सामान की आपूर्ति करने के लिए दण्ड ।

11. जो कोई भी सामान, संयन्त्र, मशीनरी, औजार, पुर्जे या अन्य सामग्री या उपकरणों की आपूर्ति के लिए ठेकेदार होते हुए :—

(क) आपूरित की गई मात्रा के सम्बन्ध में दुर्व्यवदेशन करता है, या

(ख) घटिया सामान, संयन्त्र, मशीनरी, औजार, पुर्जों या अन्य सामान या उपकरणों की आपूर्ति करता है जो कि वाणिज्यिक गुणवत्ता के नहीं है या आपूर्ति आदेश में दिए गए नमूनों या विनिदेशों के अनुसार नहीं है,

तो उसे, दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

निर्माण विभाग के अधिकारियों को धारा 11 के अधिन अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड ।

12. जो कोई भी आपूर्ति के लिए दिए उसे दिए गए आदेश के अनुसरण में ठेकेदार द्वारा की गई आपूर्ति को स्वीकृत करने का प्राधिकार रखने वाला लोक निर्माण विभाग का अधिकारी होते हुए, जानबूझ कर सामान, संयन्त्रों, मशीनरी, औजार, पुर्जे या अन्य सामान या उपकरणों की आपूर्ति को स्वीकृत करके, धारा 11 के अधीन दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करता है, तो उसे दोनों में से एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

खरीद आदेशों को दण्डित करने के लिए दण्ड ।

13. जो कोई भी निर्माण विभाग का अधिकारी होते हुए, असद्भावपूर्ण इरादे से, खरीद आदेश को इस आशय से दण्डित करता है कि वह ऐसी खरीद कर सके जो अन्यथा उसके वित्तीय प्राधिकार की सीमा से परे होती या सामान, संयन्त्र, मशीनरी, औजार, पुर्जे या अन्य सामान या उपकरणों की खरीद की स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए ऐसी खरीद

कर सके, तो उसे दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अध्याय 3

वन एवं वन्य प्राणी परिरक्षण से सम्बद्ध अपराध

वन उपज की अवैध कटाई या निपटान के लिए दण्ड।

14. जो कोई भी, वन परिरक्षण या अनुरक्षण या वन उपज के निपटान की अधिकारिता रखने वाला, प्रभारी अधिकारी होते हुए, आशय से या जानबूझ कर वाणिज्य के प्रयोजनार्थ :—

(क) वृक्षों की अवैध कटाई या कुन्दों की निकासी या,
(ख) अवैध घेराबन्दी या छेवन या,
(ग) काष्ठ, इमारती लकड़ी या बांस या अन्य उपज की चोरी,

की अनुज्ञा या मौनानुमति प्रदान करता है या दुष्प्रेरित करता है या रिपोर्ट करने में असफल रहता है तो उसे दोनों में से एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष होगी, परन्तु जो तीन वर्षों तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा :

परन्तु न्यायालय अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

बिना लेखे जोखे की कतिपय वन उपज के व्यापार के लिए दण्ड।

15. जो कोई भी, किसी वन उपज का व्यापार करता है और जिसके कब्जे में ऐसी वन उपज है या रही है जिसका वह संतोषपूर्ण लेखा-जोखा नहीं दे सकता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास, से जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने या दोनों के लिए दायी होगा :

परन्तु न्यायालय अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

1927 का 16

(क) "वन उपज" से भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 के खण्ड (6) और (7) में यथा परिभाषित "इमारती लकड़ी और वृक्ष" अभिप्रेत है और बिरोजा, कत्था और कोई अन्य वन उपज, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इसके अन्तर्गत है ; और

(ख) "वन उपज का व्यापार" से किसी रीति, प्रकार या रूप से चाहे वह कुछ भी हो, किसी वन उपज की बिक्री या क्रय या अभिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई कारोबार करना, अभिप्रेत है।

बोली-पत्रक के मिथ्याकरण और अभिवहन पास के छल साधन के लिए दण्ड।

16. जो कोई भी अधिकारी होते हुए,—

(1) वन उपज की नीलामी से सम्बन्धित बोली-पत्रक का छल साधन करता है, या

(2) किसी व्यक्ति को लाभान्वित करने या सरकारी विभाग को सदोष हानि पहुंचाने के उद्देश्य से काल्पनिक अभिवहन पास जारी करने का छल साधन करता है ;

तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

वन भूमि के सदोष सीमांकन के लिए दण्ड ।

17. जो कोई भी, निजी वनों में पेड़ों की कटाई के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए निजी और सरकारी वनों की सीमाओं के सीमांकन के लिए उत्तरदायी अधिकारी होते हुए आशय से या जानबूझकर सरकार को हानि पहुंचाते हुए सदोष सीमांकन करता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा :

परन्तु न्यायालय, अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

वन्य प्राणियों के अवैध आखेट या निर्वापण के लिए दण्ड ।

18. जो कोई भी, वन्य प्राणियों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए कर्त्तव्यवद्ध अधिकारी होते हुए,—

(क) वन्य पशुओं का अवैध आखेट करता है, अनुज्ञा देता है, मनौनुमति देता है या दुष्प्रेरणा देता है ; या

(ख) आखेट-चोरों को आश्रय देता है ; या

(ग) सुगमता से आखेट करने के लिए झुण्ड में एकत्र करने के उद्देश्य से पशुओं को घेर कर लाने या वन्य पशुओं के आवास-स्थान में आग लगाने के प्रबन्ध में सहायता करता है ; या

(घ) वन्य-प्राणियों के अवैध आखेट या वन्य-प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में उल्लिखित वन्य-प्राणियों के पशु-पदार्थ या प्रतीक के अवैध कब्जे की सूचना को गुप्त रखता है या उसकी रिपोर्ट करने में असफल रहता है ; 1972 का 53.

तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने या दोनों के लिए दायी होगा :

परन्तु न्यायालय, अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

अध्याय–4

अस्पताल आदि से सम्बन्धित अपराध

औषधियों या चिकित्सीय उपकरणों के दुर्विनियोग या हटाए जान के लिए दण्ड ।

19. जो कोई भी सरकारी अस्पताल, औषधालय या सरकार द्वारा संगठित या सहायता प्राप्त किसी अन्य ऐसी संस्था या केन्द्र में औषधियों या चिकित्सीय उपकरणों के स्टाक-रजिस्टर, बिल या वाउचर करने के लिए कर्तव्यवद्ध अधिकारी होते हुए उनका दुर्विनियोग करता है या कपटपूर्वक औषधियों या चिकित्सीय उपकरणों को हटाता है या आशय से या जानबूझ कर ऐसे दुर्विनियोग या हटाए जाने की अनुज्ञा देता है, मौनानुमति देता है या दुष्प्रेरणा करता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा:

परन्तु न्यायालय अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

20. जो कोई भी, सरकारी अस्पताल, औषधालय या सरकार द्वारा संगठित या सहायता प्राप्त किसी अन्य ऐसी संस्था या केन्द्र का चिकित्सा अधिकारी, कम्पाऊण्डर, ट्रेसर या नर्स या कोई अन्य कर्मचारी होते हुए बिना युक्तियुक्त कारण से और प्राधिकारी को सम्यक रूप से सूचना दिए बिना काम से अनुपस्थित रहता या रहती है या कपटपूर्वक या अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति से उसके उपचार के लिए फीस लेता है या लेती है तो उसे दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

काम से अनुपस्थित या कपटपूर्वक या अप्राधिकृत रूप से फीस लेने के लिए दण्ड।

21, जो कोई भी आघात-रिपोर्ट या शव-परीक्षा रिपोर्ट, या रोगी का बैड-हैड टिकट तैयार करने के लिए कर्तव्यबद्ध होते हुए, कपटपूर्वक उसे गलत ढंग से तैयार करता है या साथ सभी ब्यौरों का उल्लेख नहीं करता है या नियम या विनियम या सरकारी आदेश या परिपत्र के अधीन उसके लिए ऐसी सूचना देना अपेक्षित होने पर भी प्राधिकारी या पुलिस को सूचना नहीं देता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

समुचित रूप से अभिलेख नहीं रखने के लिए दण्ड

22. जो कोई भी औषधियों या चिकित्सीय उपकरणों की खरीद के लिए उत्तरदायी होते हुए, कपटपूर्वक घटिया किस्म की या अप्रमाणिक या विनिर्देश से निम्न स्तर की औषधियों और उपकरणों की खरीद करता है तो उसे दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष की होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा:

औषधियों के कपटपूर्ण खरीद के लिए दण्ड।

परन्तु न्यायालय, अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा।

अध्याय 5

मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब की बिक्री से सम्बन्धित अपराध

23. जो कोई भी अवैध शराब की बिक्री की जांच करने और रोकने के लिए कर्तव्यबद्ध होते हुए, जानबूझकर अवैध शराब की बिक्री के अपराध की जांच और रिपोर्ट नहीं करता है या उसकी मौनानुमति देता है या उसे दुप्प्रेरित करता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब की बिक्री और अवैध शराब की बिक्री की जांच की असफलता के लिए दण्ड।

अध्याय 6

कर से बचने के लिए बोगस फर्मों के पंजीकरण से सम्बन्धित अपराध

बोगस फर्म नाम के प्रयोग या पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए दण्ड।

24. जो कोई भी बिक्री कर से बचने या दुस्सन्धिपूर्ण बोली देने, या दुस्संधिपूर्ण निविदा प्रस्तुत करने के लिए छल करने के प्रयोजनार्थ बोगस या अविद्यमान फर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन करता है या बोगस या अविद्यमान फर्म के नाम का प्रयोग करता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित होगा।

बोगस फर्मों के पंजीकरण करने या धारा 24 के अधीन अपराध को दुष्प्रेरित करने के लिए दण्ड।

25. जो कोई भी अधिकारी होते हुए आशय से, जानबूझ कर या उपेक्षा से, समुचित जांच किये बिना, धारा 24 के अधीन अपराध को दुष्प्रेरित करने के आशय से किसी बोगस फर्म को पंजीकृत करता है या बोगस या अविद्यमान फर्म के नाम का उपयोग करने की अनुज्ञा देता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

काल्पनिक दस्तावेजों और बिना निधि के चैक के प्रस्तुतीकरण के लिए दण्ड।

26. जो कोई भी हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968, हिमाचल प्रदेश मोटर स्पिरिट (बिक्री कराधान) अधिनियम, 1968, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा वहन किये गये सामान पर) कराधान अधिनियम, 1976 के अधीन देय कर या हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के अधीन देय किसी शुल्क या फीस के प्रयोजनार्थ, आशय से या जानबूझ कर—

1968 का 24
1968 का 10
1956 का 74
1976 का 34
1914 का 1

(1) उक्त अधिनियमितियों के अधीन के कर, शुल्क या फीस से बचने लिए छल साधन के प्रयोजनार्थ कोई मिथ्या या काल्पनिक दस्तावेज या घोषणा देता है या प्रस्तुत करता है ; या

(2) ऐसा चैक देता है जिसका उसके लेखे में निधि की कमी के कारण अनादर किया जाये,

तो उसे, दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

कर एकत्र न करने और कर से बचने को सुकर बनाने के लिए अधिकारियों को दण्ड।

27. जो कोई भी किसी चैक-पोस्ट या बैरियर का प्रभारी अधिकारी या धारा 26 में निर्दिष्ट कर शुल्क या फीस को प्रभारित करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध कोई पदधारी होते हुए, आशय से या जानबूझ कर धारा 26 के अधीन अपराध को दुष्प्रेरित करने के आशय से ऐसे कर शुल्क या फीस को प्रभारित नहीं करता है या उक्त अधिनियमिति के प्रयोजन के लिए मिथ्या या काल्पनिक दस्तावेज या किसी घोषणा की अनुमति देता है या ऐसे कर, शुल्क या फीस से बचने के लिए छल साधन को मौनानुमति देता है या दुष्प्रेरित करता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जायेगा और जुर्माने के लिए दायी होगा :

परन्तु न्यायालय अभिलिखित विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर करेगा।

अध्याय 7

काल्पनिक ऋण और उनके उपयोग के मिथ्या सत्यापन और भूमि के अधिक्रमण से सम्बन्धित अपराध

काल्पनिक व्यक्तियों को ऋण देने के लिए दण्ड।

28. जो कोई भी ऋण या अर्थ-साहाय्य स्वीकृत करने या देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होते हुए आशय से या जानबूझ कर या भ्रष्ट हेतु से या अन्यथा :—

(क) किसी काल्पनिक नाम से, या

(ख) किसी काल्पनिक या अविद्यमान व्यक्ति को, या

(ग) किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर,

ऋण या अर्थ-साहाय्य स्वीकृत करता या देता है या जो कोई भी ऋण या अर्थ-साहाय्य को ऐसी स्वीकृति या उसके दिय जाने का वास्तविक लाभ प्राप्त करता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या, दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

ऋण के उपयोग के मिथ्या सत्यापन के लिए दण्ड।

29. जो कोई भी, ऋण या अर्थ-साहाय्य के समुचित उपयोग का सत्यापन करने और उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध होते हुए, जिस प्रयोजन से वह ऋण स्वीकृत किया गया या दिया गया हो, उससे प्रसंग में, उसके समुचित उपयोग के सम्बन्ध में मिथ्या रिपोर्ट या सत्यापन करता है या प्रमाणित करता है, जबकि वास्तव में उस प्रयोजन से उसका पूर्ण उपयोग नहीं किया गया हो या अंशत: उपयोग किया गया हो, या उपयोग बिलकुल ही नहीं किया गया हो, वह यदि उक्त ऋण या अर्थ-साहाय्य उसे स्वीकृत करने या देन वाले प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से किसी अन्य प्रयोजन में नहीं लगाया गया हो, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित होगा।

अधिक्रमण का पता लगाने और रिपोर्ट करने की असफलता के लिए दण्ड।

30. जो कोई भी —

(1) आरक्षित और सीमांकित संरक्षित वन-भूमि के अधिक्रमण को रोकने के लिए कर्त्तव्यबद्ध वन विभाग का अधिकारी होते हुए, या

(2) सरकारी भूमि के अधिक्रमण को रोकने के लिए कर्त्तव्यबद्ध राजस्व विभाग का अधिकारी होते हुए, या

(3) नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति, या नगरपालिका का, इन निकायों की भूमि के अधिक्रमण को रोकने के लिए, कर्त्तव्यबद्ध अधिकारी होते हुए,

आशय से या जानबूझ कर उसके अधिकारिता क्षेत्र में किसी अधिक्रमण की अनुज्ञा देता है, मौनानुमति देता है या दुष्प्रेरणा करता है या पता लगाने या रिपोर्ट करने में अपनी चूक के कारण उसे होने देता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि कम से कम एक वर्ष तक की होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा :

परन्तु न्यायालय, अभिलिखित किन्हीं विशेष कारणों से एक वर्ष से कम अवधि के कारावास का दण्डादेश भी अधिरोपित कर सकेगा ।

अध्याय 8

जन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने से सम्बन्धित अपराध

अनुज्ञप्त व्यौहारी द्वारा जनवितरण प्रणाली में गड़बड़ी ।

31. जो कोई भी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन निर्गत किसी आदेश के अधीन अनुज्ञप्त व्यौहारी होते हुए, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन घोषित आवश्यक वस्तुओं को, जैसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट करे, जन-वितरण प्रणाली स्कीम के अनुसार, सम्बद्ध जनता को आपूरित करने के बदले आशय से, जानबूझ कर या भ्रष्ट हेतु से ऐसी आवश्यक वस्तुओं को अन्य माध्यमों में अंतरित करता है या उनके वितरण का मिथ्या या काल्पनिक लेखा रखता है तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा । 1955 का 10.

किसी अधिकारी द्वारा धारा 31 के अधीन अपराध का दुष्प्रेरण ।

32. जो कोई भी जन-वितरण प्रणाली के समुचित कार्य-चालन के पर्यवेक्षण का प्रत्यक्षत: या मुख्यत: प्रभारी अधिकारी होते हुए, धारा 31 के अधीन दण्डनीय अपराध की जांच और रिपोर्ट करने में जानबूझ कर चूक करता है या उसकी मौनानुमति देता है या उसे दुष्प्रेरित करता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण उपबन्ध

कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन आहरण करने के लिए दण्ड ।

33. जो कोई भी अधिकारी होते हुए, जानबूझ कर कर्त्तव्य से अपनी अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के लिए, जब तक कि वह अवधि अनुमति की स्वीकृति या सवेतन अवकाश की स्वीकृति द्वारा नियमित न कर दी गई हो, अपना वेतन स्वयं आहरण करता है या अपनी अनुपस्थिति से सम्बन्धित तथ्यों को छुपा कर या उनका अन्यथा गलत विवरण देकर आदान तथा संवितरण अधिकारी को अपना वेतन आहरण और संवितरित करने की अनुज्ञा देता है या उत्प्रेरित करता है, और इस प्रकार सरकार के साथ छल करता है, तो वह दोनों में से किसी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

स्वीकृति का सबूत ।

34. इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के अधीन निर्गत किसी सरकारी सेवक के अभियोजन की स्वीकृति, जो सम्यक रूप से अधिप्रमाणित और सीलकृत तात्पर्यित हो, बिना किसी औपचारिक सबूत के साक्ष्य में ग्राह्य होगी: 1974 का 2.

परन्तु यदि अपराध से सम्बन्धित तथ्यों का स्वीकृति पत्र देखने से पता न चले, तो न्यायालय स्वीकृति को अधिप्रमाणित करने वाले अधिकारी को अपने सामने साक्ष्य देने के लिए बुला सकेगा ।

स्वीकृति प्ररूप में तकनीकी त्रुटियों का दूर किया जाना ।

35. राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में नियोजित किसी व्यक्ति के अभियोजन के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 के अधीन दी गई औपचारिक स्वीकृति में कोई तकनीकी त्रुटि होने से विचारण तब तक दूषित नहीं होगा जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि इससे अभियुक्त पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 1974 का 2

अपराध का संधान ।

36. इस अध्यादेश के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का कोई भी न्यायालय तब तक संधान नहीं लेगा जब तक कि इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के ज़रिए विनिर्दिष्ट अधिकारी ने लिखित रिपोर्ट न की हो :

परन्तु राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी रिपोर्ट उच्च न्यायालय की पूर्व सहमति के बिना नहीं की जाएगी ।

अध्याय 3 के अधीन के अपराधों के सिवाय अन्य अपराध जमानतीय होंगे ।

37. अध्याय 3 के अधीन किए गए अपराधों के सिवाए जो अजमानतीय होंगे, इस अध्यादेश के अधीन किए गए अपराध जमानतीय होंगे ।

अपराध सत्र-न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे ।

38. इस अध्यादेश के अधीन किसी अपराध का, सुपुर्दगी के पश्चात्, सत्र-न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा ।

उपबंध कतिपय विधियों के अल्पीकरण में नहीं होंगे ।

39. इस अध्यादेश के उपबन्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947, भारतीय दण्ड संहिता, 1860, भारतीय वन अधिनियम, 1927, हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में । 1947 का 2, 1860 का 45, 1927 का 16, 1914 का 1, 1955 का 10, 1974 का 2

नियम बनाने की शक्ति ।

40. (1) राज्य सरकार इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) इस अध्यादेश के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष, जब वह सत्र में हो,

चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया था या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व सदन उस नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाये या सदन सहमत हो जाए कि यह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, और ऐसा विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, तो नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यथा स्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा या

निष्प्रभाव हो जायेगा, किन्तु नियम के ऐसे उपान्तरण या निष्प्रभावन से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

शिमला:
28 अक्तूबर, 1983.

होकिशे सेमा,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।

वेद प्रकाश भटनागर,
सचिव (विधि) ।

[*Authoritative English text of the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Ordinance*, 1983 (*No.* 7 *of* 1983) *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*]

Ordinance No. 7 of 1983.

THE HIMACHAL PRADESH PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ORDINANCE, 1983

Promulgated by the Governor, Himachal Pradesh in the Thirty-fourth Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for punishment of specific corrupt practices resorted to by the persons serving in connection with the affairs of the State or of public undertakings or local authorities, co-operative societies or other institutions or organisations aided or set up by State Government and by some other persons in their dealings with the State Government and aforesaid bodies, with a view to eradicate and effectively prevent such practices and for other miscellaneous matters connected therewith;

Whereas the legislature of the State of Himachal Pradesh is not in session;

And whereas the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

And whereas instructions of the President of India to promulgate the Ordinance have been obtained;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Prevention of Specific Corrupt Practices Oridnance, 1983.

(2) It shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force at once.

Definitions.

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires;—

(*a*) "local authority" means any public undertaking, authority, co-operative society, corporation, body, board, society or organisation, by whatever name they are known:—

(*i*) incorporated or set up by the State Government, or

(*ii*) constituted under any Law, Ordinance, Act, Rules, or Regulations of the State Government, or

(*iii*) constituted under any Central Act, Ordinance, Rules, or Regulations, over which the State Government has control and authority;

(*b*) "officer" means a person serving in connection with the affairs of the State, local authority, or any other institution or organisation aided or set up by the State Government;

(c) "public undertaking" means a Government company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956, in which not less than fifty-one per cent of the paid up share capital is held by the State Government or any Company which is a subsidiary of a Company in which not less than fifty-one per cent of the paid up share capital is held by the State Government and includes a corporation or other statutory body, by whatever name called, in each case owned or controlled by the State Government and any other Government Company, other than a Company owned and controlled by the Central Government in which the State Government has contributed equity. 1 of 1956.

CHAPTER—II

OFFENCES RELATING TO WORK

Definitions.

3. In this Chapter, unless the context otherwise requires:—

(a) "construction" means all activities pertaining to the construction of a work and includes excavation, filling, levelling and other allied activities;

(b) "contractor" in relation to work means a person who undertakes to execute the work under a works department, in pursuance of a contract and includes, where the context so requires, a sub-contractor and includes, all other agencies and persons employed by him or working under his control for the execution of such work and the expression "works contract" shall be construed accordingly:

(c) "officer-in-charge" means an officer in relation to a work under a works contract who is primarily and directly responsible on the work site to see that the work or specific part of the work is duly executed in accordance with the terms, conditions and specifications of the works contract and the instructions, directions or work order issued by the supervisory officers or by the works department, from time to time;

(d) "officer of the works department" means the officer, whatever be the designation, employed in the works department and concerned with the survey, construction, repairs, maintenance, supervision, planning drawing, designing, purchase, supply or storage of goods mechanically propelled or electrically operated vehicles of all descriptions, plants, machinery, tools, spares or all officials responsible to make payment of bills and advances, in relation to the work;

(e) "supervisory officer" means an officer whose duty it is to supervise the work as per instructions contained in the Manual applicable to the works department or contained in any order or direction issued by the works department, from time to time;

(f) "work" means any work relating to survey, construction, repairs or maintenance of any building, superstructure, dam, weir, canal, reservoir, tank, lake, road, bridge, culvert, well including tube-well, factory, workshop, water supply system, electric installation system or any other work which the State Government may by notification specify in this behalf and includes surveying planning, drawing, designing, purchase, supply or storage of goods, mechanically propelled or electrically, operated vehicles of all descriptions

plant, machinery, tools, spares or all other materials and equipments relating to the construction, maintenance or repairs of any of the aforesaid works;

(g) "works department" means a department of the State Government, a public undertaking, a local authority, or a co-operative society registered under the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968, which gives a works contract or under whose orders, directions or control works contract is entered into or work is done, and shall include— 3 of 1969.

(i) an institution or organisation substantially aided by the State Government, as the State Government may, by notification, specify, and

(ii) any statutory or non-statutory body, by whatever name called, incorporated or set up by the State Government.

Punishment to contractor for violation of contract, etc.

4. Whoever, being a contractor of a works contract entered into with a works department, intentionally, knowingly or for corrupt motive executes the work in material violation of the terms of the contract or in flagrant disregard of the standards, specifications, orders or directions given by the works department, or its officers, so as to adversely affect the quality, workmanship, strength or life of the work or part of it, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Punishment to officer-in-charge for lack of supervision.

5. Whoever, being an officer-in-charge of a work under a works contract being executed by a contractor or otherwise, intentionally or knowingly—

(a) permits or connives at, or

(b) omits to prevent or to report about, or

(c) abets for corrupt motive,

the work being done in—

(i) material violation of the terms of the contract, or

(ii) flagrant disregard of the standard specifications, orders or directions given by the works department or its officers,

in either case so as to adversely affect the quality, workmanship, strength or life of the work or part of it, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Punishment for preparing false or fictitious muster rolls or measurement books.

6. (1) Whoever, being an officer-in-charge of a work or being an officer of the works department, in connection with a work, intentionally or knowingly—

(a) prepares a false or fictitious muster-roll, or

(b) prepares a false or fictitious measurement book, or

(c) makes payment for false or fictitious lead or false or fictitious excavation of metal, sand, earth, or

(d) incorrectly classifies a strata under excavation for making payment at a higher rate, or

(e) pays for no work or inadequate or for fictitious or bogus work, or

(f) pays at rates that are grossly inappropriate or makes deliberate overpayments, in violation of rules and orders,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

(2) Whoever, being a supervisory officer, abets the commission of an offence under sub-section (1), shall also be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Punishment for surreptitious sale of supplied material by contractor.

7. Whoever, being a contractor under a works contract, sells or otherwise transfers cement, steel, iron, or any other material supplied by the works department for the work as per specifications, instead of properly utilising the same in the work or instead of returning the unused or excess material back to the works department, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Punishment for submitting manipulated tenders.

8. Whoever, being a tenderer for a work under a works department,—

(*a*) procures, obtains or attempts to procure or obtain for himself or for any other person work under a works contract by submitting fictitious competitive tenders in the name of false or non-existent or bogus person,

(*b*) or enters into a conspiracy with any other tenderer or tenderers in order to eliminate the competition for the purpose of pushing one of the collusive low-rate tender for acceptance, or

(*c*) employs or takes active help of a near relative or of any other person in a position to unduly influence the officer having authority to accept the tender,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Explanation. – Near relation in this section means son, grand-son, father, mother, spouse, brother, sister, brother-in-law, father-in-law and mother-in-law.

Punishment to officer for accepting manipulated tender.

9. Whoever, being any officer of a works department, having authority to accept a tender on behalf of a works department—

(*a*) abets the commission of an offence under section 8 by accepting or recommending for acceptance such tender, or

(*b*) dishonestly manipulates evaluation of tenders with the object of giving benefit to a particular tenderer,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Punishment for wrongful or unauthorised disposal of poperty.

10. Whoever, being an officer of a works department, dishonestly, wrongfully or fraudulently—

(*a*) disposes of or otherwise transfers; or

(*b*) permits unauthorised use of goods, plant, machinery, tools, spares or other material and equipments from the stores, causing substantial loss to the works department,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Punishment for supply of sub-standard or lesser quantity of goods.

11. Whoever, being a contractor for the supply of goods, plants, machinery, tools, spares or other materials or equipments—

(*a*) makes misrepresentation in respect to the quantity supplied, or

(*b*) supplies sub-standard goods, plants, machinery, tools, spares or other materials or equipments which are not of mercantile quality or not in accordance with the samples or specifications given in the order of supply,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Punishment to officer of works department for abeting offences under section 1.

12. Whoever, being an officer of a works department, having authority to accept the supplies made by the contractor in pursuance of an order of supply given to him, abets the offence punishable under section 11 knowingly by accepting the supply of goods, plants, machinery, tools, spares or other materials or equipments shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Punishment for spliting up purchase orders.

13. Whoever, being an officer of the works department, with *mala fide* intention, resorts to splitting of purchase order in order to enable him to affect the purchases which would have otherwise been beyond the pale of his financial authority to do so, or in flagrant breach of the established procedure for the purchase of goods, plants, machinery, tools, spares or other materials or equipments shall be punished with imprisonment or either description which may extend to one year or fine or both.

CHAPTER III

OFFENCES CONNECTED WITH THE PRESERVATION OF FORESTS AND WILD LIFE

Punishment for illicit felling or disposal of forest produce.

14. Whoever, being an officer-in-charge for the preservation and maintenance of forest or disposal of forest produce, having jurisdiction intentionally or knowingly permits, connives or abets or fails to report, the—

(*i*) illegal felling of trees or extraction of logs, or

(*ii*) illegal girdling or trapping, or

(*iii*) theft of wood, timber or bamboos, or other forest produce,

for commercial purpose shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine:

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

Punishment for trading in certain forest produce unaccounted for.

15. Whoever trades in any forest produce and is or has been in possession of that produce which he cannot satisfactorily account for shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine or both:

Provided that the Court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

Explanation.—For the purpose of this section (*a*) "forest produce" means "timber" and "trees" as defined in clauses (6) and (7) of section 20 of the Indian Forest Act, 1927 and shall include resin, catechu or any other forest produce, which the State Government may, by notification, specify in this behalf; and

(*b*) "trading in forest produce" means the sale or purchase of any forest produce in any manner, shape or form, whatever, or carrying on any business in it with view to make profit.

Punishment for falsification of bid-sheets and manipulation of transit passes.

16. Whoever, being an officer,—

(*i*) manipulates bid-sheets in relation to auction of forest produce, or

(*ii*) manipulates issue of fictitious transit passes with a view to give benefit to any person or for causing wrongful loss to the Government Department,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Punishment for wrongful demarcation of forest lands.

17. Whoever, being an officer responsible for giving demarcation of boundaries of private and Government forests for the purpose of felling of trees in the private forests or for any other purpose intentionally or knowingly gives wrong demarcation so as to cause loss to the Government shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine:

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

Punishment for illegal hunting or extinction of wild life.

18. Whoever, being an officer duty bound to preserve and protect wild life,—

(*a*) commits, permits, connives or abets illegal hunting of wild animals; or

(*b*) gives shelter to the poachers; or

(*c*) helps in arranging drives of animals or putting fire to wild animals habitats with a view to herding for easy hutning; or

(*d*) conceals information or fails to report illegal hunting of wild animals or illegal possession of animals articles or trophies of wild animals mentioned in Schedule I of the Wild Life Protection Act, 1972; 53 of 1972.

shall be punishable with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine or both:

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

CHAPTER IV

OFFENCES RELATING TO HOSPITALS, ETC.

Punishment for misappropriation or removal of medicines or equipment.

19. Whoever, being an officer duty bound to maintain stock register, bills or vouchers of medicines or medical equipment in a Government hospital, dispensary or any other such institution or centre, organised and assisted by the Government, mis-appropriates or fraudulently removes medicines or medical equipment or intentionally or knowingly permits, connives or abets such mis-appropriation or removal, shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year and it may extend to three years and shall also be liable to fine:

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

Punishment for absence from duty or fraudulently or unauthorisedly charging fees.

20. Whoever, being a medical officer, compounder, dresser or nurse on duty or any other employee of a Government hospital, dispensary or any other such institution or centre, organised and assisted by the Government, absents himself or herself from duty without reasonable cause and without due intimation to the authority or fraudulently or unauthorisedly charges fees from any person for his treatment therein shall be punished with imprisonment of either description which may extend to one year or with fine or both.

Punishment for failure to maintain record properly.

21. Whoever, being duty bound to prepare injury report or post-mortem report or bed-head ticket of the patient, fraudulently prepares the same incorrectly or intentionally omits to mention all the details or does not inform the authority or the Police, where he is so required to inform under the rules or regulations or Government orders or circulars, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to one year or with fine or both.

Punishment for fraudulent purchases of medicines.

22. Whoever, being responsible for the purchase of medicines or medical equipments fraudulently purchases medicines or equipments which are substandard or spurious or below specification shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine:

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

CHAPTER V

OFFENCES RELATING TO SALE OF LIQUOR UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION

Punishment for sale of liquor unfit for human consumption and failure to check sale of illicit liquor.

23. Whoever, being duty bound to check and prevent the sale of illicit liquor, knowingly omits to check and report, connives or abets the commission of offence of sale of illicit liquor shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

CHAPTER VI

OFFENCES RELATING TO REGISTRATION OF BOGUS FIRMS FOR TAX EVASION

Punishment for applying for registration of or use of bogus firm name.

24. Whoever, applies for the registration of a bogus or non-existent firm, or uses a bogus or non-existent firm name, for the purpose of manipulating, sales-tax evasion, or for collusive bidding, or for submitting collusive tender, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Punishment for registering bogus firms for abeting offences under section 24.

25. Whoever, being an officer intentionally, knowingly or negligently, without holding proper inquiry, registers a bogus firm or permits the use of bogus or non-existent firms name, with the intention to abet the offence under section 24, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Punishment for production of fictitious documents and checks without funds.

26. Whoever, for the purposes of the tax payable under the Himachal Pradesh General Sales Tax Act, 1968, the Himachal Pradesh Motor Spirit (Taxation of Sales) Act, 1968, the Central Sales Tax Act, 1956, and the Himachal Pradesh Taxation (On Certain Goods Carried by Road) Act, 1976, or any duty or fee under the Punjab Excise Act, 1914, as in force in the State of Himachal Pradesh, intentionally or knowingly,— 24 of 68. 10 of 68. 74 of 56. 34 of 76. 1 of 1914.

(*i*) furnishes or produces a false or fictitious document or declaration, with a view to manipulating evasion of taxes, duties or fees under the said enactments; or

(*ii*) tenders or cheque which is dishonoured due to lack of funds in his account,

shall be punished with imprisonment of either description which may extend to one year or with fine or both.

Punishment to officers for non-collection of taxes and for facilitating tax evasion.

27. Whoever, being an officer-in-charge of check-post or barrier or an official duty-bound to charge the tax, duty or fee referred to in section 26, intentionally or knowingly does not charge such tax, duty or fee, or allows any false or fictitious document or a declaration for the purposes of the said enactments with the intention to abet an offence under section 26 of this Ordinance or connives or abets the manipulation of evasion of such tax, duty or fee, shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine:

Provided that the court, may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one year.

CHAPTER VII

OFFENCES RELATING TO FICTITIOUS LOANS AND FALSE CERTIFICATION OF THEIR UTILIZATION AND ENCROACHMENT OF LANDS

Punishment for advancing loans, etc. to fictitious persons.

28. Whoever, being an officer having authority to sanction or advance loan or subsidy intentionally, knowingly, or for corrupt motive or otherwise, sanctions or advances loan or subsidy—

(*a*) in a fictitious name, or

(*b*) to a fictitious or non-existing person, or

(*c*) in the name of another person, and whoever receives actual benefit of such sanction or advance of the loan or of subsidy, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Punishment for false verification of loan utilisation.

29. Whoever, being under a duty to verify and report proper utilisation of a loan or subsidy, falsely reports, verifies or testifies to the proper utilisation thereof, with reference to the purpose for which it was sanctioned or advanced, when in fact it was not so utilised fully, or was utilised only partly, or was not utilised at all, in relation to that purpose, unless it was diverted to some other purpose with the prior sanction of authority which sanctioned or advanced the loan or subsidy, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to one year or with fine or both.

Punishment for failure to detect and report encroachment.

30. Whoever—

(*i*) being an officer of the Forest Department duty bound to prevent an encroachment over the reserved and demarcated protected forest land ; or

(*ii*) being a revenue officer duty bound to prevent any encroachment over land belonging to the Government; or

(*iii*) being an officer of the Municipal Corporation, Notified Area Committee or Municipal Committee, duty bound to prevent encroachment over the land belonging to these bodies;

intentionally or knowingly permits, connives, abets or suffers on account of his omission to detect or report an encroachment in areas within his jurisdiction shall be punished with imprisonment of either description which shall not be less than one year but which can be extended to three years and shall also be liable to fine:

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing impose a sentence of imprisonment of less than one year.

CHAPTER VIII

OFFENCES RELATING TO TAMPERING WITH THE PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM

Tempering with the systems by the licensed dealer.

10 of 1955

31. Whoever, being a dealer licensed under any order issued under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, instead of supplying the essential commodity declared by or under the said Act, as the State Government may, by notification, specify for the purpose of this Chapter, to the public concerned in accordance with the scheme of the public distribution system intentionally, knowingly or for corrupt motives, transfers such essential commodity to other channels or maintains false or fictitious account for the distribution of the same, shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

Abetment of offences under section 31 by an officer.

32. Whoever, being an officer, directly or primarily in-charge of supervision for the proper working of public distribution system, knowingly omits to check and report, connives or abets the commission of the offence punshiable under section 31 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to three years or with fine or both.

CHAPTER IX

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Punishment for drawing salary for the period of absence from duty.

33. Whoever, being an officer intentionally draws himself or, by suppression of facts or otherwise, misrepresenting the facts relating to his absence, permits or induces the drawing and disbursing officer to draw and disburse the salary to him for the period of his deliberate unauthorised absence from duty unless the same is regularised by grant of permission or sanction of leave with pay, and thereby cheats the Government shall be punished with imprisonment of either description which may extend to one year or fine or both.

Proof of sanction.

2 of 1974

34. The sanction for prosecution of a Government servant for an offence under this Ordinance, issued under section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973, and purporting to be duly authenticated, and sealed shall be admissible in evidence without formal proof:

Provided that where the facts constituting the offence do not appear on the face of the sanction, the court may call the officer authenticating the sanction to give evidence before it.

Curability of technical defects in the form of sanctions.

35. Any technical defects in the formal sanction granted under section 197 of the Code of Criminal Procedure, 1973 for the prosecution of a person employed in connection with the affairs of the State shall not vitiate the trial unless it is proved that it caused substantial prejudice to the accused. 2 of 1974

Cognizance of offences.

36. No court shall take cognizance of an offence under this Ordinance against any person unless a report in writing is made by such an officer of the State Government as it may, by a notification, specify:

Provided that no such report shall be made against a member of judicial service of State save with the prior concurrence of the High Court.

Offences to be bailable, except under Chapter-III.

37. An offence under this Ordinance, shall be bailable except offences under Chapter-III which shall be non-bailable.

Offences to be triable by a Court of Seasions.

38. An offence under this Ordinance shall, on commitment, be tried by a Court of Sessions.

Provisions not to be derogatory to certain Laws.

39. The provisions of this Ordinance shall, be in addition to and not in derogation of the provisions of the Prevention of Corruption Act, 1947, the Indian Penal Code, 1860, the Indian Forest Act, 1927, the Punjab Excise Act, 1914, as in force in the State of Himachal Pradesh, the Essential Commodities Act, 1955 and the Code of Criminal Procedure, 1973. 2 of 1947, 45 of 1860, 16 of 1927, 1 of 1914, 10 of 1955, 2 of 1974

Power to make Rules.

40. (1) The State Government may, by notification, make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Ordinance.

(2) Every rule made under this Ordinance shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or two successive sessions, and if before the expiry of the session in which it is so laid, or the session immediate following, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, and such decision is notified in the Official Gazette, the rule shall from the date of publication of such notification, have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

SHIMLA:

The 28th October, 1983.

HOKISHE SEMA,
Governor of Himachal Pradesh.

V. P. BHATNAGARI,
Secretary (Law).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 28 अक्तूबर, 1983

संख्या-एल० एल० आर०-डी०(6)34/83.—हिमाचल प्रदेश युनिवर्सिटी (अमेण्डमैण्ट) अध्यादेश, 1983 (1983 का अध्यादेश संख्यांक 6) जैसा राज्यपाल महोदय, हिमाचल प्रदेश द्वारा "भारत के संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अन्तर्गत

दिनांक 28 अक्तूबर, 1983 को प्राख्यापित किया गया, को एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

वेद प्रकाश भटनागर,
सचिव।

H. P. Ordinance No. 6 of 1983.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE. 1983

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Thirty-fourth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh University Act, 1970 (Act No. 17 of 1970).

Whereas the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make and promulgate the following Ordinance:—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may abe called the Himachal Pradesh University (Amendment) Ordinance, 1983.

(2) It shall come into force at once.

Insertion of new section 9-A.

17 of 1970.

2. After the existing section 9 of the Himachal Pradesh University Act, 1970 (hereinafter called the principal Act), the following new section 9-A, along with its heading, shall be added, namely:—

"9-A *Power of the Chancellor to annul proceedings or decisions of the University and its bodies.*—Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul proceedings of the University or of its any authority or the decision of any officer of the University, which is not in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinances made thereunder :

Provided that before making such order, the Chancellor shall call upon the University, or as the case may be its authority or the officer, to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown with in the period specified by him in this behalf, shall consider the same."

Substitution of section 12 and insertion of sections 12-A, 12-B and 12-C.

3. For the existing section 12 of the principal Act, the following new sections 12, 12-A, 12-B and 12-C, along with their headings, shall be inserted, namely:—

"12 *Appointment of the Vice-Chancellor.*—(1) The Vice-Chancellor shall shall be appinted by the Chancellor in consultation with the State Government.

(2) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried Officer of the University.

(3) Except as expressly provided in sub-sections (4) and (5), the Vice-Chancellor shall, subject to the pleasure of the Chancellor, hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office and shall, on the expiry of the term of his office, be eligible for re-appointment to that office:

Provided that the Vice-Chancellor shall, notwithstanding the expiry of the said period of three years, continue to hold his office until his successor is appointed and enters upon his office.

(4) No person shall be appointed, or if appointed shall hold or continue to hold office, as Vice-Chancellor if he has attained age of sixty-five years.

(5) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of the Act or abuses the powers vested in him or if it appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is deterimental to the interests of the University, the Chancellor may, after making such enquiry as he deems proper and in consultation with the State Government, by order, remove the Vice-Chancellor.

(6) The Chancellor shall have power to suspend the Vice-Chancellor, during the pendency or in contemplation of any enquiry referred to in sub-section (5).

(7) The Vice-Chancellor may resign by a notice of one month in writing under his hand addressed to the Chancellor. The Chancellor may waive off the period of notice and accept the resignation forthwith in consultation with the State Government.

12-A. *Emoluments and other terms and conditions of service of the Vice-Chancellor.*—(1) There shall be paid to the Vice-Chancellor such salary as the Chancellor may, in consultation with the State Government, determine from time to time and he shall be entitled, without payment of rent, to use a furnished residence throughout the term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor personally in respect of the maintenance of such residence.

(2) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefits of the University Provident Fund or to any other allowance;

Provided that where an employee of the University is appointed as the Vice-Chancellor, he shall be allowed to continue to contribute to the Provident Fund and the contribution of the University shall be limited to what he had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor.

(3) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling allowances at such rates, and medical cost at such scales, as may be fixed by the Chancellor.

(4) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay for one-eleventh of the period spent by him on active service.

(5) The Vice-Chancellor shall also be entitled on medical grounds or otherwise than on medical grounds, to leave without pay for a period not exceeding three months during the term of his office:

Provided that such leave may be converted into leave on full pay to the extent to which he will be entitled to leave under sub-section (4).

12-B. *Arrangement of work during vacancy in the office of the Vice-Chancellor.*—(1) During the temporary absence of the Vice-Chancellor

by reason of leave, illness or any other cause, the Chancellor may, in consultation with the State Government, make such arrangements for carrying on the duties of the Vice-Chancellor as he may be deem fit.

(2) During the period a vacancy in the office of the Vice-Chancellor remains unfilled, such person as the Chancellor may appoint shall act as Vice-Chancellor and the person so appointed shall have all the powers of the Vice-Chancellor and shall be entitled to the privileges of the Vice-Chancellor and to such emoluments and allowances as may be determined by the Chancellor.

12-C. *Powers and duties of the Vice-Chancellor.*—(1) The Vice-Chancellor, who shall be the principal executive and academic officer of University, shall take rank next to the Chancellor and shall exercise general supervision and control over the affairs of the University, and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the meetings of the Court and any convocation of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Chairman of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee. He shall be entitled to be present at and to address any meeting of any authority or body of the University, but shall not be entitled to vote thereat unless he is member of such authority or body.

(3) The Vice-Chancellor shall exercise general supervision and control over the affairs of the University and shall be responsible for its proper and efficient functioning. He shall also exercise all powers necessary for due maintenance of discipline in the University.

(4) He shall ensure the observance of the provisions of this Act, the Statutes, Ordinances and Regulations and he shall have all powers necessary for that purpose.

(5) The Vice-Chancellor, either himself or through any officer of the University authorised in writing by him, convene the meetings of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee and shall perform all such acts as may be necessary to carry out the provisions contained in this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations and to give effect to the decisions of the said authorities.

(6) The Vice-Chancellor shall at the close of each academic year, in the manner prescribed in the Statutes or Ordinances assess and evaluate the teaching and research work done by the members of the Faculty. On such assessment or the evaluation, if the Vice-Chancellor is of the opinion that the work and conduct of any member of the Faculty is not satisfactory, he shall, in the manner as laid down in the Statutes or Ordinances, initiate or cause to be initiated action against such a member.

(7) In case of any emergency which, in his opinion, requires immediate action, the Vice-Chancellor shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report the action taken to such authority or body as would in the ordinary course have dealt with the matter:

Provided that if the action taken by the Vice-Chancellor is not approved by the authority or body concerned it may refer the matter to the Chancellor whose decision shall be final:

Provided further that if the decision taken by the authority or body on the report of the Vice-Chancellor under this sub-section affects adversely any person in the service of the University, the person may prefer an appeal to the Chancellor within thrity days from the date on which decision was communicated to him and the decision of the Chancellor on such appeal shall be final.

(8) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations.

Amendment of section 19.

4. In existing section 19 of the principal Act after the word "Court" but before the word "and", the words "of not more than sixty-five members" shall be inserted.

Substitution of section 21.

5. For the existing section 21 of the principal Act, the following section 21 shall be substituted, namely:—

"21. (1) The Executive Council shall be the Executive Body of the University and shall consist of the following members:—

Ex-officio Members

(*i*) the Vice-Chancellor;
(*ii*) the Registrar;
(*iii*) the Secretary (Finance) to the State Government;
(*iv*) the Secretary (University Education) to the State Government;
(*v*) the Director of Education, Himachal Pradesh;

Other Members

(*vi*) two Deans of Faculty to be nominated by rotation by the Vice-Chancellor:
(*vii*) two principals of affiliated colleges/colleges maintained by the University by rotation on the basis of seniority of whom one shall be principal of a Government College;
(*viii*) one member to be elected by the court from amongst its members who is not a teacher or an employee or a student in the University;
(*ix*) one member to be elected by the Academic Council from amongst its members other than students and employees of the University:
(*x*) one professor of the University by rotation on the basis of seniority to be nominated by the Vice-Chancellor;
(*xi*) one person to be nominated by the State Government;
(*xii*) one representative of students and one representative of non-teaching employees to be appointed for a period of one year at a time in the manner prescribed by the Statutes; and
(*xiii*) two persons to be nominated by the Chancellor out of the persons having special knowledge, or practical experience in respect of such matters as art, literature, law, science and administration or social service.

(2) Save as otherwise provided and except the ex-officio members, all other members shall hold office for a period of two years from the date of their election or nomination, as the case may be:

Provided, however, that no person nominated or elected in his capacity as a member of a particular body or as a holder of a particular appointment shall be a member after he ceases to be a member of that body or holder of that appointment, as the case may be:

Provided further that any member other than ex-officio members, shall cease to be a member of the Executive Council if he absents himself from more than three consecutive meetings of the Executive Council without leave of absence from the Council.

(3) No person shall be or continue to be a member of the Executive Council in more than one capacity, and, whenever a person becomes a member of the Executive Council in more than one capacity, he shall, within two weeks thereof, choose the capacity in which he desires to be member of the Executive Council and shall vacate the other seat. Where he does not so choose, the seat held by him earlier in point of time shall be deemed to have been vacated with effect from the date of expiry of the aforesaid period of two weeks.

(4) Seven members of the Executive Council shall form the quorum.

(5) The Executive Council shall be in charge of the general management and administration (including the revenue and property) of the University.

(6) The powers and functions of the Executive Council shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Amendment of section 22.

6. For the sign "." occurring at the end of sub-section (2) of section 22 of the principal Act, the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the total membership of the Academic Council shall in no case exceed sixty-five.".

Amendment of section 39.

7. For the existing sub-section (3) of section 39 of the principal Act, the following sub-section (3) shall be substituted, namely:—

"(3) Every Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of the Statutes, shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold assent or remit to the Executive Council for reconsideration with his suggestions. In case the Executive Council passes it again in the same form and manner or the Chancellor is satisfied that it is not in the interests of the University, he may disallow such Statutes, amendment or repeal."

Amendment of section 40.

8. After sub-section (2) of section 40 of the principal Act, the following new sub-section (3) shall be added, namely:—

"(3) The amendment or the repeal of the Ordinances under sub-section (2) shall have no validity unless it has been assented to by the Chancellor in consultation with the State Government".

Substitution of section 41.

9. For the existing section 41 of the principal Act, the following new section 41, along with its heading shall be substituted, namely:—

"41. *Regulations.*—(1) The Executive Council may, with the sanction of the Chancellor, may, Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances for all matter relating to the University.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such Regulations may, in relation to the authorities of the University provide for,—

(*a*) laying down the procedure to be followed at their meeting and number of members required to form quorum;

(*b*) all matters which by this Act, the Statutes, or the Ordinances are to be provided by the Regulations;

(*c*) any other matter solely concerning any authority and not provided by this Act, the Statutes and the Ordinances; and

(*d*) the giving of the notice to its members of the dates of the meetings and the business to be transacted thereat and for the keeping of the record of the proceedings of such meeting."

Insertion of section 49.

10. At the end of existing section 48 of the principal Act, the following new section 49, along with its heading, shall be inserted, namely:—

"49. *Miscellaneous.*—If any elected or nominated member of the Court, Executive Council and the Academic Council or any Body or Committee of the University ceases for any reason to be a student, teacher or an employee in which capacity he was elected/nominated he shall cease to be a member and his office shall become vacant".

TRANSITORY PROVISIONS

Reconstitution and continuation of members, of the authorities of the University.

11. (1) Notwithstanding anything contained in the principal Act, as amended by this Ordinance, the Court, the Executive Council and the Academic Council of the University shall, as soon as may be after the commencement of this Ordinance, be reconstituted in accordance with the provisions contained in sections 19, 21 and 22 of the principal Act, as amended by this Ordinance, and every person holding office as a member of such authority immediately before the commencement of this Ordinance shall, on the date of such commencement, cease to be member and the said authorities shall stand dissolved.

(2) As soon as may be after the commencement of this Ordinance, the State Government shall constitute interim Court, Executive Council and Academic Council of the University in such manner as it thinks fit and the members of the said authorities constituted under this sub-section shall hold office for a period of six months or until the constitution of the authorities in accordance with provisions of sections 19, 21 and 22 of the principal Act, as amended by this Ordinance, whichever is earlier.

Power to remove difficulties.

12. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty by order published in the Official Gazette, direct that the provisions of the principal Act, as amended by this Ordinance, shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of six months from the commencement of this Ordinance.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

SHIMLA:
THE 28TH OCTOBER, 1983.

HOKISHE SEMA,
Governor.

V. P. BHATNAGAR,
Secretary (Law).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।